

600वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 अक्टूबर 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 600वीं बैठक दिनांक 18/10/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No 9252/2022 M/s Vrindavan Construction, Partner, Shri Arun Agrawal S/o Late Shri R.P.Agrawal, 250, Sagar Plaza, Zone-II, M.P. Nagar, Dist. Bhopal, MP. Environment Clearance for Proposed at Proposed “Sage Golden Spring” Residential Apartment located at Khasra No. - (10/1, 12, 13, 14, 15), (10/2/1, 12, 13, 14, 15), 11/1, (16/1, 18, 21), (16/2, 18, 21) 17/1/1, 17/1/2, 17/2/2, 17/3/1, 17/3/2, 28/1/1, 28/1/2, 28/2/1, 28/2/2, 29/1/1, (A) 29/1/1 (B) 29/1/2/1, 29/1/2/2, 84/1/1, (84/2/1, 85, 86/1), 84/2/2, 86/2, Village – Damkheda, Patwari Halka No. 21, Tehsil – Huzur & District – Bhopal (M.P.). Total Plot Area – 47170.00 Sq.mtr. (4.717 ha.), Built Up Area - 98714.54 square meter ha., Cat. - 8(a). Building and Construction projects. Env. Con. -Global Management and Engineering Consultants International, Jaipur, (Rajasthan).**

This is case of Environment Clearance for Construction of "M/s Vrindavan Construction is developing “Sage Golden Spring” Residential Apartment Located at Village: Damkheda, Patwari Halka No. 21, Tehsil – Huzur & District – Bhopal, Madhya Pradesh on a land admeasuring 47,170 Square meter (4.717 Ha).

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 583rd SEAC dated 30/06/2022 wherein ToR was recommended. PP has submitted the EIA report forwarded by SEIAA on-line and the same was scheduled in the agenda.

600वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 अक्टूबर 2022

The case was presented by Env. Consultant Shri G.K. Mishra, Global Management and Engineering Consultants International, Jaipur, (Rajasthan) and Shri Sanjay Gupta authorized representative on behalf of PP. PP submitted that about 4.5% construction has been completed without obtaining EC and thus the case falls under the violation category. During presentation, it was observed by the committee that PP has not submitted the specific and justifiable reply of all TOR point and needs detailed justification. Thus after presentation, PP was asked to submit response on following issues with revised details:

1. Detailed, specific and justifiable reply of all TOR point issued for carrying out EIA.
2. Justifiable details of 4.5% constructed area with supported evidences.
3. Commitment of PP that 30 meters shall be left from the HFL of nearby drain and this area will be developed as green belt.
4. Revised carbon foot print analysis as discussed during presentation.
5. Please provide 10KW grid solar panel backup calculation and with solar street lights.
6. Revised damage assessment and remediation plan as discussed during presentation.
7. Backup calculation of proposed population of 3645 peoples and if revision is proposed, please includes all activities such as banquet hall, Multiples etc. Similarly, if population is revised, please submit revised details of MSW, Water requirement and Waste Water Treatment Facility etc.
8. Clarification regarding G+ 1 detail proposed for flats in EIA.

2. **Case No 9349/2022 Smt. Sumitra Chouksey, Leelatola, Tehsil - Pushparaigarh, Dist. Anuppur, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (7001 Cum per annum) (Khasra No. 7), Village - Sindhpur Ryt, Tehsil - Bajag, Dist. Dindori (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 7), Village - Sindhpur Ryt, Tehsil - Bajag, Dist. Dindori (MP) 1.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 18/10/22 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सुमित्रा चौकसे (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कागनीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि. गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 393 दिनांक 06/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि डिंडोरी जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-04 के सरल क्रमांक 17 पर इस खदान का विवरण दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के दक्षिण भाग में लगभग 260 मीटर पर

600वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 अक्टूबर 2022

आबादी, 120 मीटर पर कच्चा रास्ता तथा पश्चिम दिशा में 415 मीटर पर स्टॉपडेम है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्टॉपडेम के संरक्षण हेतु गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टेक प्रस्तावित किये गये हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 7,001 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 06.69 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.60 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सिंधपुर रैयत साप्ताहिक बाज़ार में अधोसंरचना विकास	50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बेरियर जोन	नीम, महुआ, करंज, चिरोल, खमेर, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	940
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 1 मीटर)	करंज, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	60
3	ग्राम के स्टॉप डैम में	नीम, सीताफल, करंज अन्य स्थानीय प्रजातिया	150
4.	विद्यालय	मौलश्री, पुत्रन्जीवा, कचनार, कदम, नीम अन्य स्थानीय प्रजातिया	50
कुल			1200

3. **Case No 9350/2022 Shri Raghuveer Singh Ranawat, 300, Jawahar Marg, Gali No. 01, Nagda, Dist. Ujjain, MP - 456001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.34 ha. (20000 Cum per annum) (Khasra No. 283), Village - Jhirmira, Tehsil - Khacharod, Dist. Ujjain (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 283), Village - Jhirmira, Tehsil - Khacharod, Dist. Ujjain (MP) 1.34 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

600वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 अक्टूबर 2022

प्रकरण आज सेक की 600वीं बैठक दिनांक 18/10/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

4. Case No 9351/2022 Shri Pawan Anjana S/o Shri Bhagwan Singh Anjana, Village - Chak Kamed, Tehsil - Ghatiya, Dist. Ujjain, MP - 456001, Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 4.0 ha. (10000 Cum per annum) (Khasra No. 86), Village - Madhawgarh, Tehsil - Ghatiya, Dist. Ujjain (MP)

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 86), Village - Madhawgarh, Tehsil - Ghatiya, Dist. Ujjain (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज सेक की 600वीं बैठक दिनांक 18/10/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

5. Case No 9353/2022 M/s Satguru Cement Pvt. Ltd, Shru Rajesh Bansal, Partner, 601/1, Airen Heightus, PU 3 Scheme No. 54, Dist. Indore, MP - 454001 Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 4.0 ha. (40000 Cum per annum) (Khasra No. 104/1), Village - Jheeran, Tehsil - Gandhwani, Dist. Dhar (MP)

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 104/1), Village - Jheeran, Tehsil - Gandhwani, Dist. Dhar (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज सेक की 600वीं बैठक दिनांक 18/10/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

600वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 अक्टूबर 2022

6. Case No 9354/2022 Smt. Rama Singh W/o Shri Vikarm Singh, Karaudia Uttar Tola, Tehsil - Gopad Banas, Dist. Sidhi, MP - 486675, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (Expansion From 5130 Cum per annum to 39999 Cum per annum) (Khasra No. 267), Village - Amahwa, Tehsil - Gopadbanas, Dist. Sidhi (MP)

This is case of Stone Quarry Expansion From 5130 Cum per annum to 39999 Cum per annum. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 267), Village - Amahwa, Tehsil - Gopadbanas, Dist. Sidhi (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 18/10/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री रमा सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री शैलेन्द्र सोनकर, अधिकृत प्रतिनिधि, मेसर्स फारेस्ट इंवायरमेंट एवं क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट कन्सलटेंट प्रा. लि. भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 61 दिनांक 27/05/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है तथा कुल रकबा 04.95 हे. होता है, इस प्रकार प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के दक्षिण-पश्चिमी भाग में लगभग 400 मी. तथा दक्षिण भाग में 325 मीटर की दूरी पर आबादी है तथा पूर्वी दिशा में 275 मीटर की दूरी पर रोड़ है। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन क्षेत्र में कई पेड़ लगे हैं तथा 02 पिट दिख रहे हैं। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह प्रकरण क्षमता विस्तार का है, इसलिए पुराने पिट दिखा रहे हैं तथा खनन क्षेत्र में लगे पेड़ों की इन्वेट्री प्रस्तुतीकरण में दी गई हैं। परियोजना प्रस्तावक ने बताया किया कि प्रकरण क्षमता विस्तार का है, अतः पुरानी पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों का पालन प्रतिवेदन भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल से के पत्र क्रमांक 18-डी-12/2022 (डिया) के माध्यम से प्राप्त किया गया है, जिसके कोई नॉन कम्पलाईस नहीं है। समिति ने प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया किया पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जो डिया द्वारा जारी की गई थी, उसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक को 45 पेड़ लगाने थे जबकि उनके द्वारा मात्र 15 पेड़ ही लगाये गये हैं, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा इस वर्षाकाल में 200 पेड़ लगा दिये गये हैं, जो स्थानीय वन समिति से क्रय किए गए हैं, जिनकी क्रय की रसीद एवं फोटोग्राफ प्रस्तुतीकरण में संलग्न किए गए हैं। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके आवंटित खनन क्षेत्र में 15 पेड़ लगे हैं, जिसमें से 10 पेड़ सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरांत काटे जायेंगे एवं उसके एवज में 100 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा सीधी जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसके पेज नं. 24 के सरल क्रमांक-19 पर इस खदान का विवरण दर्ज है परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं

600वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 अक्टूबर 2022

स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता विस्तार स्टोन – 5130 मी³ प्रति वर्ष से 39,999 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 07.63 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.36 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु-में)
ग्राम अमहवा के शासकीय प्राथमिक स्कूल छात्रों के डिजिटल अध्ययन हेतु रोजेक्ट 02	40000
ग्राम अमहवा के आगनवाड़ी केंद्र के छत सुधार एवं पानी के नवीन टंकी की व्यवस्था	80000
योग	1,20,00

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2500 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बेरियर जोन	सागौन, खमेर, सुबबूल, करंज नीम एवं बांस अन्य स्थानीय प्रजातिया	500
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 1 मीटर)	काला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया ट्री गार्ड के साथ-	400
3	ग्राम अमहवा के स्कूल, ग्राम पंचायत भवन आगनवाड़ी के प्रांगण एवं बंजर शासकीय भूमि में।	नीम कदम, पीपल, करंज, अशोक एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	300
4.	अमहवा के ग्राम वासियों में वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ, अमरुद, नीम अन्य स्थानीय प्रजातिया	1200
कुल			2500

7. **Case No 9355/2022 Smt. Samta Gupta W/o Shri Manish Gupta, Sadar Bazar, Tehsil - Susner, Dist. Agar Malwa, MP - 465447 Prior Environment Clearance for Stone & M-sand Quarry in an area of 2.90 ha. (Stone - 5000 Cum per annum, M-sand - 15000 Cum per annum) (Khasra No. 1326/4), Village - Soyatkalan, Tehsil - Susner, Dist. Agar Malwa (MP)**

This is case of Stone & M-sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1326/4), Village - Soyatkalan, Tehsil -

600वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 अक्टूबर 2022

Susner, Dist. Agar Malwa (MP) 2.90 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 18/10/22 को परियोजना प्रस्तावक समता गुप्ता (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2044 दिनांक 05/08/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, तथा कुल रकबा 04.90 हे. होता है, इस प्रकार प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के दक्षिण-पूर्वी भाग में लगभग 120 मी. की दूरी पर पक्का रोड है। परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि इस प्रकरण में 15,000 घनमीटर / वर्ष का एम-सेंड प्लांट भी प्रस्तावित है जो व्ही.एस.के. तकनीक पर आधारित है। एम-सेंड प्लांट से निकलने वाला दूषित जल का पुर्नउपयोग किया जायेगा तथा स्लज का अपवहन माइन पिट में ओव्हर वर्डन के साथ किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा आगर मालवा जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसके पेज नं. 55 के सरल क्रमांक-66 पर इस खदान का विवरण दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 5,000 मी³ प्रति वर्ष एवं एम-सेंड – 15,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 09.77 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 04.59 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
ग्राम सोयतकलां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ अधिकारी के परामर्श से केंद्र में जरूरत के हिसाब से उपयोग हेतु सामग्री एवं उपकरण प्रदान किये जावेंगे	1,10,000
योग	1,10,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3480 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आवला, खमेर, , नीम, चिरोल, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	800

600वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 अक्टूबर 2022

2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1 मीटर)	जंगल जलेबी, पीपल, करंज, चिरोल, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया टी-गार्ड के साथ	300
3	ग्राम सोयतकलां के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र परिसर में	नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, करंज, आवला एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	50
4	ग्राम सोयतकलां के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला परिसर में	चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, करंज, नीम, पीपल, सप्तपर्णी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	100
5	ग्राम सोयतकलां के कृषि उपज मंडी परिसर में	चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, करंज, नीम, पीपल, सप्तपर्णी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	200
6	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	अमरुद, आमला, अनार, इमली, सीताफल, आम, कटहल, निम्बू, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	2030
कुल			3480

8. Case No 9357/2022 M/s M.K.C. Infrastructure Limited, Authorized Signatory, Shri Dharmendra Mehta, Shiv Nagar Anjar, Dist. Kutch, Gujarat, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.70 ha. (50000 Cum per annum) (Khasra No. 57/1), Village - Antraliya, Tehsil - Suwasra, Dist. Mandsaur (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 57/1), Village - Antraliya, Tehsil - Suwasra, Dist. Mandsaur (MP) 4.70 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 18/10/22 को को परियोजना प्रस्तावक समता गुप्ता (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि इस अस्थाई अनुज्ञा हेतु कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2162 दिनांक 28/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पश्चिमी भाग में लगभग 380 मी. की दूरी पर जल रोकने की संरचना है तथा आवंटित खनन क्षेत्र से सरफेस रन ऑफ ड्रेन निकल रहा है जिसके संरक्षण हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टेक प्रस्तावित किये गये हैं । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मंदसौर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन किया गया है, जिसके पेज नं.-59 के सरल क्रमांक 08 पर इस खदान का विवरण दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा

600वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 अक्टूबर 2022

पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 50,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 16.97 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 02.85 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 02.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
ग्राम अंत्रालिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से जरूरत के हिसाब से उपयोग हेतु सामग्री एवं उपकरण प्रदान किये जावेंगे।	1,00,000
आवेदित क्षेत्र के पश्चिमी दिशा में 380 मीटर स्थित चेक डैम के आस पास पौधरोपण किया जावेगा एवं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जावेगी	1,00,000
योग	2,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 02 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5640 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, बरगद, करंज आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजीतिया ।	500
2	परिवहन मार्ग में	पीपल, करंज, बरगद, चिरोल, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजीतिया ट्री-गार्ड के साथ	600
3	ग्राम अंत्रालिया के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, पपीता, आम, मुनगा, कटहल, आवला करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजीतिया	40
4	खदान में प्रस्तावित गैर खनन क्षेत्र में	चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजीतिया	500
5	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, इमली, निम्बू, कटहल एवं अन्य स्थानीय प्रजीतिया	4000
कुल			5640

600वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 अक्टूबर 2022

9. Case No 9358/2022 Shri Ayush Jain S/o Shri Ashok Kumar Jain, Hatpura, Tehsil - Agar, Dist. Agar Malwa, MP – 465441 Prior Environment Clearance for Stone & M-sand Quarry in an area of 3.0 ha. (Stone - 10000 Cum per annum, M-sand - 10000 Cum per annum) (Khasra No. 92), Village - Badgon, Tehsil - Agar, Dist. Agar Malwa (MP)

This is case of Stone & M-sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 92), Village - Badgon, Tehsil - Agar, Dist. Agar Malwa (MP) 3.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 06/10/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री आयुश जैन (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2036 दिनांक 04/08/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर दिशा में लगभग 185 मी. की दूरी पर पक्का रोड है तथा दक्षिण दिशा में 310 मीटर पर आबादी है। आवंटित खनन क्षेत्र के पूर्वी भाग में खदान से लगी हुई एक मृदा एवं जल संरक्षण संरचना निर्मित है, जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा मध्यप्रदेश एम.एम.आर., 1996 के अनुसार 100 मीटर का सेटबैक छोड़ा गया है तथा पुनरीक्षित सरफेस मैप प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न है जिसके पश्चात् लगभग 01.80 हे. का क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध होगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस छोड़े गये नॉन माईनिंग जोन में चारागाह विकास (गहरी जोताई के साथ स्थानीय पशुओं के खाने योग्य घास का रोपण तथा 05-05 मीटर की दूरी पर फोडर ट्री लगाये जायेगे) का कार्य किया जायेगा, क्योंकि आवंटित भूमि चारागाह मद में गोचर के रूप में दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि इस प्रकरण में 10,000 घनमीटर / वर्ष का एम-सैंड प्लांट भी प्रस्तावित है जो व्ही.एस.के. तकनीक पर आधारित है। एम-सैंड प्लांट से निकलने वाला दूषित जल का पुर्नउपयोग किया जायेगा तथा स्लज का अपवहन माइन पिट में ओव्हर वर्डन के साथ किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा आगर मालवा जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसके पेज नं. 55 के सरल क्रमांक-67 पर इस खदान का विवरण दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 10,000 मी³ प्रति वर्ष एवं एम-सैंड – 10,000 मी³ प्रति वर्ष।

600वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 अक्टूबर 2022

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.66 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 04.37 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
ग्राम बड़गाओं के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ अधिकारी के परामर्श से केंद्र में जरूरत के हिसाब से उपयोग हेतु सामग्री एवं उपकरण प्रदान किये जावेंगे	1,20,000
योग	1,20,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3630 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर , सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू , पीपल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1 मीटर)	पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया ट्री-गार्ड के साथ	500
3	ग्राम बड़गौन के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र परिसर में	आवला, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू , पीपल, करंज, चिरोल एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	60
4	ग्राम झलारा के मुक्ति धाम परिसर में	चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, करंज, नीम, पीपल, सप्तपर्णी, बरगद, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	150
5	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	संतरा, आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, निम्बू, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1920
कुल			3630

10. Case No 8884/2021 Shri Pankaj Nagar, Owner, Nivasi- Bordikalan, Teh- Ichhawar, Dist- Sehore, MP - 466115 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (5001 Cum per annum) (Khasra No. 356/3/1), Village - Bordikalan, Tehsil - Ichhawar, Dist. Sehore (MP) . RQP Shri Shirish Deulkar, Jabalupr

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 356/3/1), Village - Bordikalan, Tehsil - Ichhawar, Dist. Sehore (MP) 1.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

600वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 अक्टूबर 2022

The case was presented by RQP Shri Shirish Deulkar on behalf of PP. During presentation, PP showed various documents such as lease sanction order, Gram Sabha, DFO NOC, Tehsildar Certificate, MO Certificate, Approved Mine Plan, Khasra Panchshala, P-II, DSR, EMP & PFR for appraisal of project before the committee. It was observed by Committee that as per Collector Office (Ekal Praman-patra) letter No. 3236 dated 11/11/21 has reported that there are 01 more mines operating or proposed within 500 meters around the said mine with total area of 3.0 ha., including this mine.

As per Google image based on coordinates provided by PP in online form II, it was observed that the area of the lease is about 1.27 ha., whereas lease is sanction of area of 1.0 ha., only as per mining plan. Moreover, PP submitted that they have taken this KML based on coordinates mentioned in the approved Mining Plan. Hence, now in such condition they will submit revised KML based on revised coordinates duly approved from the competent authority i.e. from DGM. The committee after deliberation decided that PP shall submit correct KML, based on revised coordinates duly approved from the competent authority then after their case shall be further considered.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रकरण को सेक की 566वीं बैठक दिनांक 02/03/22 के द्वारा प्रकरण डिलिस्ट कर दिया गया था। परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल दिनांक 07/09/22 के अनुसार प्रकरण को सिया के पत्र क्रमांक 1682 दिनांक 23/09/22 द्वारा रिलिस्ट कर सेक को प्रेषित किया गया है।

प्रकरण को आज दिनांक 18/10/22 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री पंकज नागर (ऑनलाईन) एवं पर्यावरण सलाहकार श्री शिरिश देवलकर उपस्थित हुए। प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुरानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज नहीं है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जब प्रकरण ऑन लाईन अपलोड किया गया था उस समय नई जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित नहीं हुई थी वर्तमान में अनुमोदित जिला सिहोर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-65 के सरल क्रमांक 34 पर इस खदान का विवरण दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा पुनरीक्षित कोआर्डिनेट संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म के पत्र क्रमांक 10891 दिनांक 10/08/22 के माध्यम से प्राप्त किये गये हैं जो ऑन लाईन ए.डी.एस के साथ दिनांक 06/10/22 को अपलोड किये गये हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर-पूर्व दिशा में लगभग 290 मी. की दूरी पर पक्का रोड है, दक्षिण दिशा में 230 मीटर पर प्राकृतिक नाला है, पूर्व दिशा में 20 मीटर कच्चा रोड है तथा आवंटित खनन क्षेत्र में पुराना केशर स्थापित है। आवंटित खनन क्षेत्र के उत्तर दिशा में 135 मीटर पर आबादी है जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा मान्नीय एन.जी.टी. के निर्देशानुसार 65 मीटर का सेट बैक प्रस्तावित किया गया है तथा पुनरीक्षित सरफेस मैप प्रस्तुतीकरण में संलग्न किया गया है। प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि आवंटित क्षेत्र के आसपास एक और खदान दिख रही है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह काफी पुरानी खदान है जो 2010 के पूर्व की है

600वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 अक्टूबर 2022

तथा बंद हो चुकी है। वर्तमान में प्रश्नाधीन खदान के अतिरिक्त सिर्फ एक खदान कार्यरत है जिसका उल्लेख एकल प्रमाण पत्र में भी है। समिति ने पाया कि गूगल एमेज के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में पूर्व से पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन किया जा रहा है ऐसा प्रतीत नहीं होता है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का निम्नानुसार छ:माही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे हैं अथवा नहीं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-5001 मी.3 प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 11.90 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 03.09 प्रति वर्ष।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.20 लाख सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
आंगनवाड़ी कर्मचारियों के अनुरोध के अनुसार बोरदीकलान की आंगनवाड़ी के लिए स्कूल डेस्क व कुर्सी का सेट 5	20,000
	20,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	खमार, सिस्सू, अमलतास, नीम, कालासिरिस, चिरोल, करंज, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	250
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 1 मीटर)	अमलतास, खिरनी, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय ट्री गार्ड के साथ-एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	200
3	ग्राम बोरदीकलान के स्कूल, ग्राम पंचायत भवन आंगनवाड़ी के प्रांगण एवं बंजर शासकीय भूमि में।	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	450
4	बोरदीकलान के ग्राम वासियों में वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरुद नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	300
योग			1200

600वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 अक्टूबर 2022

11. Case No 9298/2022 Shri Yogesh Nagar, Owner] Hiraniya Ward No. 09, Obaidullaganj, Tehsil - Gouharganj, Dist. Raisen, MP - 464993, Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.80 ha. (33345 cum per annum) (Khasra No. 14/1) Village - Jamuniya Veeran, Tehsil - Sultanpur, Dist. Raisen (MP)

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 14/1) Village - Jamuniya Veeran, Tehsil - Sultanpur, Dist. Raisen (MP) 2.80 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

सेक की 594वीं बैठक दिनांक 21/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री योगेश नागर (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री शैलेन्द्र सोनकर, अधिकृत प्रतिनिधि, मेसर्स फारेस्ट इंवायरमेंट एवं क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट कन्सलटेंट प्रा. लि. भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 638 दिनांक 16/06/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 04.80 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। सिया के पत्र क्रमांक 529 दिनांक 23/05/22 के द्वारा रायसेन जिले के नवीन जिला सर्वेक्षण का अनुमोदन किया जा चुका है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज नहीं है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि स्वीकृत खदान के उत्तरी दिशा में एक तथा दक्षिण-पश्चिम दिशा में दो खदानें दिख रही हैं जबकि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 638 दिनांक 16/06/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, अतः उपरोक्त संदर्भ में सेक द्वारा से खनिज अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार प्रस्तावित खदान रातापानी अभ्यारण्य के ईकोसेंसेटिव जोन से कितनी दूरी पर स्थित है, की जानकारी वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त की जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 11/10/22 को अपलोड कर दी गई है, जिसे आज समिति के समक्ष दिनांक 18/10/22 को रखा गया जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री योगेश नागर (ऑनलाईन) एवं पर्यावरण सलाहकार श्री शैलेन्द्र सोनकर, अधिकृत प्रतिनिधि, मेसर्स फारेस्ट इंवायरमेंट एवं क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट कन्सलटेंट प्रा. लि. भोपाल उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सिया के पत्र क्रमांक 529 दिनांक 23/05/22 के द्वारा रायसेन जिले के नवीन जिला सर्वेक्षण का अनुमोदन किया जा चुका है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज नहीं है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के पत्र 815 दिनांक 22/07/22 के माध्यम से सूचित किया है कि प्रश्नाधीन उत्खनिपट्टा को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन कर दिया जावेगा। जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश द्वारा इस प्रकरण में (9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में उनकी 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 में निम्नानुसार निर्णय लिया है :-

600वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 अक्टूबर 2022

“राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया – चूंकि प्रकरण से संबंधित जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सेक की अनुशंसा पर सिया द्वारा अनुमोदित की गई है जो कि 05 वर्ष के लिए वैध है एवं जिला स्तर पर नवीन खदानों की स्वीकृति की निरंतर प्रक्रिया होती है अतः ऐसे जिले जिनकी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित की जा चुकी है उनके द्वारा बाद में स्वीकृत प्रकरणों में जो कि पूर्व में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किए गए हैं, उन प्रकरणों में पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किये जाना उचित होगा। पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अनुमोदित होने पर संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा अधिसूचना में निहित निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप समावेश कर जिला पोर्टल पर अपलोड कर सिया एवं सेक को सूचित किया जाये”।

समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक ने इस प्रकरण में भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किये जाने का अनुरोध किया गया। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा पुनरीक्षित जानकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के पत्र 1140 दिनांक 07/10/22 के माध्यम से प्राप्त की है जिसमें उनके द्वारा पुनः सूचित किया गया है कि 500 मीटर की परिधि में एक उत्खनन पट्टा ही स्वीकृत है अतः उनका प्रकरण बी-2 श्रेणी में आता है। इसी प्रकार परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय अधीक्षक, रातापानी वन्य प्राणी अभ्यारण, औवेदुल्लागंज में पत्र क्रमांक 2111 दिनांक 29/9/21 में यह लेख किया है कि आवेदित स्थल रातापानी अभ्यारण के ईको सेसेटिव जोन की सीमा से बाहर स्थित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर-पूर्वी दिशा में 225 मीटर पर आबादी, पश्चिम दिशा में लगभग 10 मी. की दूरी पर प्राकृतिक नाला है अतः एम.पी.एम.एम.आर. 1996 के अनुसार नाले 40 मीटर का सेट वेक छोड़ा जाना होगा जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा 40 मीटर का सेट वेक प्रस्तावित किया गया है तथा पुनरीक्षित सरफेस मैप प्रस्तुतीकरण में संलग्न किया गया है एवं खनन हेतु लगभग 2.00 हे. का क्षेत्र उपलब्ध होगा। इसी प्रकार समिति ने पाया कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन कार्य वर्ष 2019 के पश्चात् किया जाना प्रतीत होता है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खनन कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया है तथा उनको लीज इसी स्थिति में दिसंबर-21 में आवंटित हुई है तथा पिट को अनुमोदित खनन योजना के सरफेस मैप पर दर्शाया गया है। समिति ने पाया कि गूगल एमेज के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में पूर्व से पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन किया जा रहा है ऐसा प्रतीत नहीं होता है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का निमनानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे हैं अथवा नहीं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-33,345 मी.³ प्रति वर्ष।

600वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 अक्टूबर 2022

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 08.39 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.41 प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.30 लाख सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
ग्राम जमुनिया वीरान के शासकीय प्राथमिक स्कूल छात्रों के डिजिटल अध्ययन हेतु प्रोजेक्टर 02	60000
ग्राम जमुनिया वीरान के शासकीय प्राथमिक स्कूल के छात्रों को स्कूली जूते/ मोझे वितरण 246 छात्रों की कुल संख्या)	70000
कुल	1,30000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	सागौन, खमेर, नीलगिरी सुबबूल बांस एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	800
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 1 मीटर)	कला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), करंज ट्री गार्ड के साथ- एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	400
3	जमुनियावीरान स्कूल-, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	300
4	जमुनियावीरान- एवं चपला सर के ग्राम वासियों में वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरुद एवं नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	1500
योग			3000

12. जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों पर चर्चा –

अ. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, खंडवा – (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर)

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र0. 809 दिनांक 10/10/22 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट– खंडवा (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिति का अनुमोदन एवं जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।

Mineral	Other than Sand
DSR received from District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Khandwa , No. 809 dated 10.10.2022.

600वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 अक्टूबर 2022

SEAC meeting dated 18/10/22	<ul style="list-style-type: none"> जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के चैप्टर –08 (पेज न0. 31–58) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दे दी गई है। जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एवं प्रजातियों की जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अंत में टेबिल (पेज न0. 87–101) में दे दी गई है।
--------------------------------	---

आज दिनांक 18.10.22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री सचिन वर्मा, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला खंडवा के पत्र क्र0 809/खनिज/2022 दिनांक 10/10/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति खंडवा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज—रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

ब. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, शाजापुर – (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर)

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र0. 509 दिनांक 12/10/22 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट—शाजापुर (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिति का अनुमोदन एवं जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।

Mineral	Other than Sand
DSR received from District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Shajapur, No. 509 dated 12.10.2022.
SEAC meeting dated 18/10/22	<ul style="list-style-type: none"> जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के चैप्टर क्र0. –09 (पेज न0. 25–49) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दे दी गई है। जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एवं प्रजातियों की जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अंत में टेबल (पेज न0. 81–85) में दे दी गई है।

600वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 अक्टूबर 2022

आज दिनांक 18.10.22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री आर.एस. उइके, सहायक खनिज अधिकारी उपस्थित रहे ।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला— शाजापुर के पत्र क्र० 509/खनिज/2022 दिनांक 12/10/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति शाजापुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

स. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

आज दिनांक 18/10/22 को छिंदवाड़ा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अन्य गौण खनिज हेतु प्रस्तुत की गयी रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री मोहित तिवारी, सहायक ग्रेड-3 उपस्थित हुये।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 594 वीं बैठक दिनांक 21/09/22 में छिंदवाड़ा जिले की पुनरीक्षित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निम्न बिन्दुओं को उन्नयन करने संबंधी निर्देश उपस्थित जिला खनिज अधिकारी को दिये गये थे

- छिंदवाड़ा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तालिका क्र०. – XIV (Annexure) पेज क्र०. 44-45 में लीजवार जो मिनरल पोटेन्शियल प्रस्तुत किया है। तालिका में रेत की मात्रा की गणना करते समय घन मी. की मात्रा में पुनरीक्षण करना पाया गया है, साथ ही उपलब्ध क्षेत्र के आधार से दर्शायी गयी मात्रा काफी कम पायी जा रही है एवं इसको स्पष्ट करते हुये पुनरीक्षित कर पुनः प्रस्तुत करें।
- मिनरल पोटेन्शियल की गणना दर्शाने वाली तालिका में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60% माइनेबल पोटेन्शियल (रेत खनन हेतु) मी.टन यूनिट में भी दर्शावें।
- विगत 03 वर्षों के उत्खनित रेत की मात्रा का खदानवार मात्रा भी दर्शावें जिससे ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेन्शियल विगत 03 वर्षों में कितना रहा।

उपरोक्त संबंध में खनिज अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला— छिंदवाड़ा के पत्र क्र०. 1307 दिनांक 10/10/2022 के द्वारा अद्यतन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, छिंदवाड़ा द्वारा सेक कार्यालय को प्रेषित की गई थी, जिसके परीक्षण उपरांत पाया गया कि :-

- कार्यालय के 1307 दिनांक 10/10/2022 के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के एनेक्जर-XIV (पेज नं. 44 एवं 45) पेंच नदी (सरल नं.-18) पर स्थित पटनिया ग्राम की लीज में पुनरीक्षित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेत की मात्रा 15,000 घनमी. रेत की उपलब्धता अंकित है वहीं दूसरी इसी

600वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 अक्टूबर 2022

रिपोर्ट के एनेक्जर-3 (पेज नं. 76 से 78) में सरल क०. 11 में पेंच नदी पर स्थित पटनिया 1,08,108 घनमीटर दर्शायी गई थी, जिसके संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाना आवश्यक है ।

- इसी प्रकार सरल क०. 14 के ग्राम राजाखोह में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेत की मात्रा 8169.6 घनमीटर अंकित है वहीं दूसरी ओर इसी रिपोर्ट के एनेक्जर-14 में इसी खदान की रेत की मात्रा 9,856 घनमीटर अंकित है । इस प्रकार प्रस्तुत आंकड़ों में कुछ अंतर परिलक्षित हो रहा है, जिसका सुधार आवश्यक है ।

अतः चर्चा उपरांत समिति का अभिमत है कि अतः जिला खनिज अधिकारी स्पष्ट करें कि गणना में इतना अंतर क्यों आ रहा है ।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

600वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 18 अक्टूबर 2022

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

600वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 18 अक्टूबर 2022

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

600वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 अक्टूबर 2022

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

37. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

600वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 18 अक्टूबर 2022

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{\text{th}}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - f. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - g. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - h. Length, breadth and sanctioned depth of mine.

600वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 18 अक्टूबर 2022

- i. Minal Potential of sand mine.
 - j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - k. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
- i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
 - vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
38. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

600वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 अक्टूबर 2022

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.

600वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 18 अक्टूबर 2022

15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - l. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - m. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - n. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - o. Minable Potential of sand mine.
 - p. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - q. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of

600वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 अक्टूबर 2022

tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.

600वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 18 अक्टूबर 2022

2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.

600वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 18 अक्टूबर 2022

27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna".
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The undertaking inter alia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.

600वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 अक्टूबर 2022

- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained